



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी.एस.टी. भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/6/GDM/2019	Refund/20/DC/Mundra/Refund/2018- 19	29.11.2018

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-048-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:	18.03.2020	जारी करने की तारीख / Date of issue:	18.03.2020
------------------------------------	------------	--	------------

श्री गोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर,
राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST /
GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-**

Dorf Ketal Speciality Pvt. Ltd, Plot No. 2, Block -F, Sector 12N, Adani Port and SEZ, Tal:Mundra, Kutch-370421, Gujarat

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा अहमदाबाद- 380016 को की जानी चाहिए। /

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/- Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.
- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूप से अधिक न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.
- (C) **भारत सरकार कोपनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:
- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयावधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।
जहां संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.

:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s. Dorf Ketal Speciality Catalyst Pvt. Ltd., Plot No.2, Block No. F, Sector-12-N, Adani Port & SEZ, Taluka – Mundra, Dist – Kutch (hereinafter referred to as “appellant”) filed appeal No. V2/6/GDM/2019 against refund order No Refund/20/DC/Mundra/Refund/2018-19 dated 29.11.2018 (hereinafter referred to as “impugned order”) issued by the Deputy Commissioner, Central GST Division, Múnra, Kutch Commissionerate (hereinafter referred to as “refund sanctioning authority”).

2. The brief facts of the case are that the appellant has filed refund claim for the Rs. 22,15,952/- on 30.08.2018 before refund sanctioning authority for the availing benefit of exemption of services tax paid for the specified services received and used exclusively for authorized operations by virtue of issuance of the Notification No 12/2013-ST dated 01.07.2013. The adjudicating authority vide impugned order restricted refund claim to the tune of Rs. 9,549/- against refund claim of Rs. 22,15,952/-.

3. Aggrieved, the appellant preferred the present appeal, *inter-alia*, on the following grounds:

(i) The refund sanctioning authority has restricted claim as the same was submitted after due date. The refund claim was filed by them after due date as their administrative office is situated at Mumbai and the person who was handling the accounts had left the job and for the same reason, they were not able to file the claim in prescribed time limit.

(ii) The refund sanctioning authority has rejected claim on the reason that the service was not in the table of approved services at the time of services availed by the appellant but the said service was added in the list later.

(iii) The refund sanctioning authority has rejected claim on the basis of mismatch of payment amount against actual invoice amount but they have not considered that appellant had done advance part payment in earlier period and final payment done in this claim period.

4. Personal Hearing in the matter was given on 04.09.2019, 26.09.2019, 04.11.2019, 02.12.2019, 16.12.2019, 16.01.2020 & 29.01.2020 but no one from the appellant side has appeared for the same. Therefore, the instant case is to be decided *ex-parte* on the basis of available records.



5. I have carefully gone through the documents available on records, facts of the case, the impugned order, and grounds of appeal memorandum. The issue to be decided in the present appeal is whether the refund sanctioning authority has correctly restricted refund claim filed by the or otherwise.

6. I find that the procedures of the refund claim for those services whose actual payment of service tax was made by such Developer or SEZ unit to the registered service provider covered under the Notification No. 12/2013-ST dated 01.07.2013; the same is reproduced below:

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)

Notification No. 12 / 2013-Service Tax

New Delhi, the 1st July, 2013

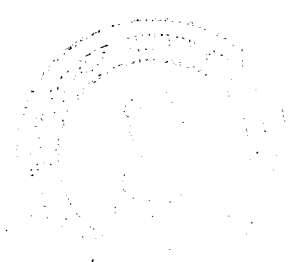
G.S.R.....(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act) read with sub-section 3 of section 95 of Finance (No.2), Act, 2004 (23 of 2004) and sub-section 3 of section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 40/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 482 (E), dated the 20th June, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the services on which service tax is leviable under section 66B of the said Act, received by a unit located in a Special Economic Zone (hereinafter referred to as SEZ Unit) or Developer of SEZ (hereinafter referred to as the Developer) and used for the authorised operation from the whole of the service tax, education cess, and secondary and higher education cess leviable thereon.

2. The exemption shall be provided by way of refund of service tax paid on the specified services received by the SEZ Unit or the Developer and used for the authorised operations:

Provided that where the specified services received by the SEZ Unit or the Developer are used exclusively for the authorised operations, the person liable to pay service tax has the option not to pay the service tax *ab initio*, subject to the conditions and procedure as stated below.

3. This exemption shall be given effect to in the following manner:

(I) The SEZ Unit or the Developer shall get an approval by the Approval Committee of the list of the services as are required for the authorised operations (referred to as the 'specified services' elsewhere in the notification) on which the SEZ Unit or Developer wish to claim exemption from service tax.



(II) The *ab-initio* exemption on the specified services received by the SEZ Unit or the Developer and used exclusively for the authorised operation shall be allowed subject to the following procedure and conditions, namely:-

(a) the SEZ Unit or the Developer shall furnish a declaration in Form A-1, verified by the Specified Officer of the SEZ, along with the list of specified services in terms of condition (I);

(b) on the basis of declaration made in Form A-1, an authorisation shall be issued by the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be to the SEZ Unit or the Developer, in Form A-2;

(c) the SEZ Unit or the Developer shall provide a copy of said authorisation to the provider of specified services. On the basis of the said authorisation, the service provider shall provide the specified services to the SEZ Unit or the Developer without payment of service tax;

(d) the SEZ Unit or the Developer shall furnish to the jurisdictional Superintendent of Central Excise a quarterly statement, in Form A-3, furnishing the details of specified services received by it without payment of service tax;

(e) the SEZ Unit or the Developer shall furnish an undertaking, in Form A-1, that in case the specified services on which exemption has been claimed are not exclusively used for authorised operation or were found not to have been used exclusively for authorised operation, it shall pay to the government an amount that is claimed by way of exemption from service tax and cesses along with interest as applicable on delayed payment of service tax under the provisions of the said Act read with the rules made thereunder.

(III) The refund of service tax on (i) the specified services that are not exclusively used for authorised operation, or (ii) the specified services on which *ab-initio* exemption is admissible but not claimed, shall be allowed subject to the following procedure and conditions, namely:-

(a) the service tax paid on the specified services that are common to the authorised operation in an SEZ and the operation in domestic tariff area [DTA unit(s)] shall be distributed amongst the SEZ Unit or the Developer and the DTA unit (s) in the manner as prescribed in rule 7 of the Cenvat Credit Rules. For the purpose of distribution, the turnover of the SEZ Unit or the Developer shall be taken as the turnover of authorised operation during the relevant period.

(b) the SEZ Unit or the Developer shall be entitled to refund of the service tax paid on (i) the specified services on which *ab-initio* exemption is admissible but not claimed, and (ii) the amount distributed to it in terms of clause (a).

(c) the SEZ Unit or Developer who is registered as an assessee under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, or the said Act or the rules made thereunder, shall file the claim for refund to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, the as the case may be, in Form A-4;

(d) the amount indicated in the invoice, bill or, as the case may be, challan, on the basis of which this refund is being claimed, including the service tax payable thereon shall have been paid to the person liable to pay the service tax thereon, or as the case may be, the amount of service tax payable under reverse charge shall have been paid under the provisions of the said Act;

(e) the claim for refund shall be filed within one year from the end of the month in which actual payment of service tax was made by such Developer or SEZ Unit to the registered service provider or such extended period as the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall permit;

(f) the SEZ Unit or the Developer shall submit only one claim of refund under this notification for every quarter:

Explanation:- For the purposes of this notification "quarter" means a period of three consecutive months with the first quarter beginning from 1st April of every year, second

quarter from 1st July, third quarter from 1st October and fourth quarter from 1st January of every year.

(g) the SEZ Unit or the Developer who is not so registered under the provisions referred to in clause (c), shall, before filing a claim for refund under this notification, make an application for registration under rule 4 of the Service Tax Rules, 1994.

(h) if there are more than one SEZ Unit registered under a common service tax registration, a common refund may be filed at the option of the assessee.

(IV) The SEZ Unit or Developer, who intends to avail exemption or refund under this notification, shall maintain proper account of receipt and use of the specified services, on which exemption or refund is claimed, for authorised operations in the SEZ.

4. Where any sum of service tax paid on specified services is erroneously refunded for any reason whatsoever, such service tax refunded shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under, as if it is recovery of service tax erroneously refunded;

5. Notwithstanding anything contained in this notification, SEZ Unit or the Developer shall have the option not to avail of this exemption and instead take CENVAT credit on the specified services in accordance with the CENVAT Credit Rules, 2004.

6. Words and expressions used in this notification and defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) or the rules made thereunder, or the said Act, or the rules made there under shall apply, so far as may be, in relation to refund of service tax under this notification as they apply in relation to a SEZ.

7. This notification shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India

[F.No. B1/6/ 2013-TRU]

(Akshay Joshi)

Under Secretary to the Government of India

6.1 I find that, as per the Para 3(III)(e) the claim for refund shall be filed within one year from the end of the month in which actual payment of service tax was made by the Developer or SEZ unit to the registered service provider; the appellant has filed the refund claim on 30.08.2018; hence the refund can be consider on or after 01.08.2017 on which actual payment of the service tax made by the appellant.

6.2 Further, I find that it is mentioned at Para 3(III)(e) that such extended period as the Assistant / Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, shall permit. The adjudicating authority has mentioned in impugned order that previously also the appellant had filed his earlier application for refund pertaining to previous period beyond the prescribed period of one year as per Para 3(III)(e) of Notification No. 12/2013-ST dated 01.07.2013 and sought condonation of delay. Therefore, the appellant was well aware of rules and regulations relating to time limit for filing of refund and has repeated the mistake of violating the provision of the law again. Therefore, the adjudicating authority has correctly rejected the

claim as time barred.




6.3 Further, I find that as per Para No. 3(I) the SEZ Unit or the Developer shall get an approval by the Approval Committee of the list of the services as are required for the authorized operations (referred to as the 'specified services' elsewhere in the notification) on which the SEZ Unit or Developer wish to claim exemption from service tax. Therefore, the appellant can claim only those services which are approved by the approval committee; therefore, adjudicating authority has correctly rejected the claim on services which were not approved by the approval committee at the time of service received by the appellant.

6.4 The appellant has claimed that the refund sanctioning authority has rejected claim on the basis of mismatch of payment amount against actual invoice amount but they have not considered that appellant had done advance part payment in earlier period and final payment done in this claim period but no documentary evidences submitted by the appellant in support of their claim; therefore, I am not discussing the same.

7. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, I uphold the impugned order and reject the appeal.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

8. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.


(GOPI NATH)
Commissioner(Appeals) 18/3/2020

Attested



(S.D.Sheth)

Superintendent (Appeals)

By RPAD

To,
M/s. Dorf Ketel Speciality Catalyst Pvt. Ltd.,
Plot No.2, Block No. F, Sector-12-N,
Adani Port & SEZ,
Taluka – Mundra, Dist – Kutch

Copy for information and necessary action to:

- 1) The Principal Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad for kind information please.
- 2) The Commissioner, CGST & Central Excise Commissionerate, Kutch.
- 3) The Deputy Commissioner, CGST & Central Excise Division, Mundra.
- 4) Guard File.